

ग्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग **I**——खण्ड 2

PART I-Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ० 14

नई विल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 1971/आवण 6, 1893

No. 14]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 1971/SRAVANA 6, 1893

इस भाग में भित्र पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July 1971

No. 3/18/71-AIS(IV).—In the following notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, namely:—

- 1. No 3/6/66-AIS(IV), dated the 31st October, 1966.
- 2. No. 3/33/67-(i)AIS(IV) dated the 10th June, 1968.

the President had been pleased to appoint officers named therein, recruited under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, to the Punjab Cadre of the Indian Forest Service with effect from the 1st October, 1966. It is now notified for general information that as a result of the decisions of the Supreme Court of India in Writ Petitions Nos. 173 to 175 of 1967 and in Special Leave Petitions No. 766/70 and 1574 to 1578 of 1970 in the Supreme Court of India, the appointments of the officers named in the aforesaid notifications to the Indian Forest Service have been rendered ab initio void. Consequently, the Central Government proposes to take further steps to make fresh recruitment under sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

म्रधिसू चना

मई दिल्ली, 28 जुलाई, 1971

सं० 3/18/71-भ्र०भा० से (4).--भारत सरकार, गृह मंत्रालय की निम्नालिखित श्रधि-सूचनाओं में, प्रथति :---

- 1. सं · 3/6/66-ए ॰ म्राई ॰ एस (4), दिनांक 31-10-1966

भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन किये गये अधिकारियों को जिन के नाम उन में विये गये हैं राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के पंजाब संवर्ग में पहली अक्तूबर, 1966 से नियुक्त किया था श्रव सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि 1967 की रिट याचिकाओं सं० 173 से 175 तक में और भारत के उच्चतम न्यायालय में 1970 की विशेष अवकाश याचिकाओं सं० 766/70 और 1574 से 1578 तक में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के फलस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचनाओं में आये अधिकारियों के नामों की नियुक्तियां प्रारम्भ से ही अमान्य घोषित की गई हैं। इसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन नयी भर्ती करने के लिए, आगे कारवाई करने का है।

म्रक्षा म्रार० जार्ज, संयुक्त सचिव।